जाता है। इसमें सवा करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा, ऐसा अनुमान है।

श्री अन्नत दवे : जो अनाज खराब हो गया है, उसका किस तरह से उपयोग किया जाएगा ? इसके बारे में सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : हमारे यहां यह तरीका है कि उसकी जांच होती है। अगर वह ह्यूमन कंजम्सन के लिए फिट नहीं होता है तो उसे खाने के लिए नहीं दिया जाता है। इसके बारे में नियम बने हुए हैं। इसके डिस्पोजल के बारे में स्टेट गवर्नमेंट से कहा जाता है और उन्हें आफर किया जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है जो अनाज खाने योग्य नहीं है वह इन्सानों तक न पहुंचे।

श्री तेज प्रताप सिंह : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि ये जो नियम बने हुए हैं उनके अनुसार चाहे गल्ला खराब क्यों न हो जाए लेकिन उसे आसपास के लोगों को नहीं दिया जाता है, चाहे उनकी क्रय शक्ति हो या न हो, क्या यह गल्ला ऐसे लोगों को दिया जायेगा जो साइक्लोन से पीड़ित हैं और जिनके पास खाने के लिए नहीं है ? क्या ऐसा गल्ला जो खाने के लायक है, इन भूख से भीड़ित लोगों को दे दिया जाएगा ? क्या इसीलिए नियम में भी परिवर्तन किया जाएगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह : साइक्लोन से पीड़ित लोगों को बहुत अच्छा गल्ला दिया जा रहा है। उनके लिए गल्ले की कमी नहीं है। लेकिन जो गल्ला इन्सान के खाने लायक नहीं है, वह गल्ला हम जरूर इन्सान के हाथों में पहुंचने से रोकना चाहते हैं।

SHRI M. S. SANJEEVI RAO: Sir, in view of the great devastation which has been caused in Andhra Pradesh, and also taking into consideration the fact that there are many factories which have collapsed which has caused heavy unemployment problem there, will the hon. Minister consider the construction of more godowns in that area so that this problem can be solved to some extent? As he is aware, it is a rice-bowl, not only of the South, but of the entire country. Will the construction of more godowns be undertaken there?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Large scale construction of godowns is already in hand and that area will certainly receive its due share of consideration and there is no doubt about it.

छोटे और सीमान्त किसानों के लिये सामुदायिक नलकूप

*473. **श्री रुद्रसेन चौधरी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में छोटे और सीमान्त किसानों के उत्थान के लिए छोटे सामुदायिक नलकूप लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b). Yes Sir. The installation of small community tubewells wherever feasible are being taken up under the normal minor irrigation programmes implemented through the State Plan Resources and institutional investment. In addition, special emphasis is being laid on construction of community wells under the Central Sector Programmes such as Small Farmers Development Agency, Drought Prone Area Programme, Integrated Tribal Development Programme, Command Area Development Programme, etc. Specially higher subsidy of 50 per cent is being provided for the community wells under these programmes.

श्री रुद्रसेन चौधरी : मेरा प्रश्न हिन्दी में था, मंत्री जी को जवाब हिन्दी में देना चाहिए था।

मेरा पहला सप्लीमेंटरी यह है कि क्या सरकार ऐसे छोटे और सीमान्त किसानों के लिए जिनके लिए अब तक कोई राजकीय व्यवस्था नहीं की गई है और जो अभी तक अपने सिंचाई के साधन जुटाने की स्थिति में नहीं हुए हैं, उनके लिए सामुदायिक नलकूप लगाने की कोई निश्चित योजना बनाएगी जिससे इन छोटे और सीमान्त किसानों को लाभ पहुंच सके ? क्योंकि बहुत से ऐसे छोट और सीमान्त किसान हैं जिनको ये साधन अभी तक नहीं मिले हैं, जबकि बड़े और मध्यम किसानों ने ट्यूबवैल लगा कर अपने निजी साधन कर लिए हैं।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह मैंने पहले अर्ज किया है कि ये जो सेन्ट्रल प्रोजेक्ट्स हैं ये उन स्माल फार्मर्स के लिए हैं जिनकी होल्डिंग्स एक से दो हेक्टेयर होती है और इन प्रोजेक्ट्स के नीचे उन्हें 25 परसेंट सब्सीडी या असिसटेंस दी जाती है। जिनके पास एक हेक्टेयर तक जमीन है उनको 33-1/3 प्रतिशत सब्सीडी दी जाती है। कम्युनिटी वर्क्स के लिए 50 परसेंट सब्सीडी दी जाती है।

श्री रुद्रसेन चौधरी : मैंने यह पूछा है कि जो सब्सीडी दी जाती है वह व्यक्तिगत आधार पर जो अपने नलकूप लगाते हैं या अन्य सिंचाई के साधन अपने लिए उपलब्ध करते हैं, उनको दी जाती है। उसके बावजूद भी जो छोटे और सीमान्त किसान हैं जिनके पास बहुत छोटे छोटे खेती के टुकड़े हैं और जो अपने व्यक्तिगत नलकूप नहीं लगा सकते हैं, अपने व्यक्तिगत साधनों से इस तरह से सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्या सरकार स्वयं सामूहिक आधार पर छोटे छोटे नलकूप लगाने की योजना बनाएगी ?

उत्तर प्रदेश के बारे में मेरा यह कहना है कि वहां जो लघु सीमान्त कृषक विकास एजेंसी है और छोटे और सीमान्त किसानों के लिए कार्य करती है क्या इस एजेंसी की मार्फत आप इस तरह का सर्वे करवायेंगे कि छोटे और सीमान्त किसानों के लिए कितने नलकूपों की आवश्यकता है और उनके लिए क्या आप छोटे छोटे नलकूप इत्यादि लगवायेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मेरा जवाब माननीय सदस्य ने सुना नहीं है। मैंने यह कहा है कि कम्युनिटी वर्क्स के लिए, लोगों को इकट्ठा करके जब ये लगाए जाते हैं तो उसके लिए पचास परसेंट तक सब्सीडी दी जाती है और जो अलग अलग लगाते हैं उनको कम दी जाती है। इसलिए कम्युनिटी वर्क के वास्ते जब इकट्ठे होकर लगाए जाते हैं तो उनके लिए पचास परसेंट दी जाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या व्यवस्था की है, क्या प्रोग्राम बनाया है और बनाया या नहीं यह तो उत्तर प्रदेश की सरकार ही बता सकती है। हम तो यह चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा प्रदेशों में बनें।

MR. SPEAKER: His question is this. Are you going to adopt U.P. model or any other model in other States?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: We are encouraging such projects. This is what I have said.

श्री रुद्रसेन चौधरी : मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछा था। लघु सीमान्त कृषक विकास एजेंसी केन्द्रीय सरकार की है, एस० एफ० डी० ए० केन्द्रीय एजेंसी है, यह प्रान्तीय सरकार की नहीं है। मैंने यह जानना चाहा है कि उसके द्वारा क्या प्रोग्राम बनाया गया है और सीमान्त और छोटे किसानों के लिए क्या छोटे नलकूप लगाए जायेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : एस० एफ० डी० ए० के द्वारा छोटे नलकूप लगाए जाते हैं जहां-

जहां कम्युनिटी चाहती है, वहां लगाए जाते हैं। ऐसे बहुत से लगाए भी गए हैं।

श्री राम कंवर बेरवा : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि छोटे छोटे नलकूप लगाने के लिए पचास प्रतिशत की हम छूट देते हैं किसानों को। मैं जानना चाहता हूं कितने कितने नलकूप आपने विभिन्न प्रान्तों में लगाए हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : किस प्रान्त में कितने लगे हैं यह जानकारी मांगी नहीं गई थी इसलिए मैं नहीं दे सकूंगा।

MR. SPEAKER: He cannot answer this question off-hand.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Mr. Speaker, Sir, just now the Minister said that he is going to adopt U.P. model. I want to ask him whether he is going to adopt Punjab and Haryana Models in other States or not.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: In Punjab and Haryana, tubewells are provided some of which are only state tubewells. Community tubewells have not been provided in many parts of Punjab and Haryana so far.

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : लघु सीमान्त कृषक जो सारे देश में हैं उन सब के लिए एक निश्चित अवधि में सिचाई की व्यवस्था करने के लिए क्या सरकार कृत संकल्प है यदि हां, तो वह निश्चित अवधि क्या है ताकि पता चल सके कि सारे देश में गरीबी और भूखमरी कब तक मिट सकेगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : ऐसी कोई योजना नहीं है कि सारे एक एकड़ वाले किसानों के लिए एक अवधि में इस प्रकार का प्रोग्राम बना दिया जाए।

SHRI S. NANJESHA GOWDA: I would like to ask the Minister regarding the tubewells and community wells. The Minister was pleased to say that funds are given to the SFDA and other agencies. But, I say that progress achieved in the entire field is not satisfactory. He is spending crores of rupees on the big projects. Why should he not spend for the tubewells and also provide the same to the small farmers and levy only for water and why not contributions be made for providing major irrigation projects for the purpose. Why is he not formulating specifically a new policy? When can he do that?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Every year 150,000 tubewells are being given. This year also we are going to have the same number and, if the hon. Member has any complaint about any particular area, he can bring that to my notice and I shall look into it.

SHRI S. NANJESHA GOWDA: Sir, he has not answered my question.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Lower Average Realisation than Cost of Production of Sugar during 1976-77

*469. SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the all India average realisations by the sugar industry from 1976-77 sugar production so far, have been much lower than the all India average cost of production both from levy and levy-free sugar;

(b) if so, what is the gap per quintal of sugar and also the total loss suffered by the industry on the entire production for 1976-77; and

(c) how do Government propose to mitigate the huge loss to the industry on this account?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) Yes, Sir.